RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 05 MAY TO 11 MAY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 37 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

मार्च, अप्रैल की जीएसटी मासिक रिटर्न, कर भुगतान में देरी पर विलंब शुल्क माफ Page 3

दूरसंचार विभाग की कंपनियों के 5जी परीक्षण को मंजूरी Page 4

कोरोना का नया अवतार B1617 दक्षिण भारत में फैल रहा तेजी से ... Page 5

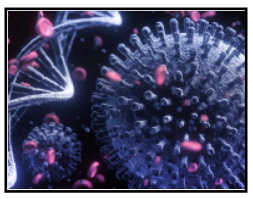

editoria!

सामूहिक प्रयास जरूरी

बीते एक साल से अधिक समय से जारी महामारी का कहर अपने सबसे भयावह दौर में है. पिछले सप्ताह जहां 26 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए, वहीं लगभग 24 हजार लोगों की मौत हो गयी. गंभीर रूप से बीमार लोगों की बहुत बड़ी संख्या को हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है. इस स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाये जा रहे हैं. अनेक देशों से मदद भी पहुंच रही है. लेकिन संकट इतना बड़ा है कि हमें अपनी कोशिशें भी तेज करनी होंगी. केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ऑक्सीजन या दवाओं की कमी या अस्पताल में बिस्तर न मिल पाने से एक भी व्यक्ति की मौत न हो. देश के अनेक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सरकारों को लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं. इन निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. देश के सामने यह एक अभूतपूर्व संकट है, इसलिए इसका सामना भी पूरी ताकत के साथ किया जाना चाहिए. एक तरफ बड़ी संख्या में संक्रमितों के उपचार की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस का अध्ययन करने और आबादी के बड़े हिस्से को टीका देने का काम भी करना है. महामारी के पहले चरण में ही अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गयी थी, अब फिर एक बार ग्रहण के आसार हैं. ऐसे में देश के पास उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग से कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. हमने अपनी तैयारियों में पहले ही बहुत देर कर दी है और अब किसी भी तरह का लचर रवैया आत्मघाती होगा. ऐसे में पहली प्राथमिकता अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेटर की व्यवस्था है. बीते दिनों में अनेक जगहों से ऑक्सीजन की कमी से रोगियों के मरने की खबरें आती रही हैं. खाली बिस्तर और वेंटिलेटर की तलाश में इस अस्पताल से उस अस्पताल दौड़ते-भागते मरीजों और उनके परिजनों की तस्वीरें दिल दहलानेवाली हैं. यह एक तथ्य है कि आबादी के बहुत बड़े हिस्से को टीके की पूरी खुराक दिये बिना महामारी पर निर्णायक जीत हासिल नहीं की जा सकती है. इसलिए टीकों का उत्पादन बढ़ाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीके सस्ते हों और सहूलियत से लगाये जा सकें. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को वैक्सीन नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. उम्मीद है कि इस संबंध में जल्दी ही कोई ठोस फैसला लिया जायेगा. केंद्र और राज्य सरकारों को जांच, संक्रमण और उपचार से संबंधित आंकड़ों के मामले में पारदर्शिता न बरतने की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए. ये आंकड़े केवल दस्तावेजीकरण के लिहाज से ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि इन्हें ही आधार बनाकर भविष्य की ऐसी किसी चुनौती का सामना करने की सही तैयारी हो सकती है. आगामी कुछ दिन बेहद अहम हैं.

तेल की मांग न होने का असर

सउदी अरबिया एशियाई देशों के लिए जून में कीमतें कर सकता है कम

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेलों के निर्यात का प्रमुख देश सउदी अरबिया को उम्मीद है कि वह जून में कच्चे तेलों की कीमतें कम कर सकता है। यह कमी एशियाई देशों के लिए होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तेलों की मांग पर असर दिख रहा है।

जून में ओएसपी में कटौती हो सकती है

सूत्रों के मुताबिक, सउदी अरबिया जून में अपने ऑफिशियल सेलिंग प्राइस (ओएसपी) में कटौती कर सकता है। रॉयटर्स के एक सर्वे में पता चला है कि जून महीने में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पांच एशियन रिफाइनरी के बारे में अनुमान है कि इसमें औसतन 28 सेंट्स प्रति बैरल की कमी की जा सकती है। पिछले साल दिसंबर के बाद यह पहला मौका होगा, जब तेल उत्पाद देश कीमतें कम करेंगे।

अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में घटी तेल की मांग

अनुमान है कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े के बाद से तेलों की मांग घट गई है। 24 फरवरी के बाद इस दौरान सबसे कम तेल की मांग रही है। सर्वे में शामिल जवाब देने वाले दो (respondents) ने कहा कि भारत में कोविड संक्रमण में आई तेजी ने स्थानीय ईंधन (local fuel) की मांग को प्रभावित किया है। मार्केट सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाई है। इससे रिफाइनरीज को स्पॉट मार्केट में कच्चे तेल की धीमी खरीद की ओर धकेल दिया है। उनमें से एक ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि मई के पहले सप्ताह की बिक्री किस तरह होगी। इसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा।

अप्रैल में कोरोना के मामलों में तेजी आई

शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में, कोरोनावायरस संक्रमणों की तेजी से फैल रही दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध से भारत में ईंधन की खपत में गिरावट आई है। सऊदी क्रूड OSPs आमतौर पर प्रत्येक महीने की पाँचवीं तारीख के आसपास जारी किए जाते हैं। इससे ईरानी, कुवैती और इराकी कीमतों के लिए रुझान निर्धारित होती है। इससे एशिया के लिए प्रतिदिन 1.2 करोड़ बैरल से अधिक क्रूड (बीपीडी) प्रभावित होता है। तेल कंपनी सऊदी अरामको ग्राहकों की सिफारिशों के आधार पर प्रोडक्शन और उत्पाद की कीमतों के आधार पर अपने कच्चे तेल की कीमतें सेट करती है।

भारत में भी तेलों की कीमतें घट सकती हैं

कच्चे तेलों की कीमतों में अगर गिरावट आती है तो भारत में भी तेलों की कीमतें घटाने का अवसर होगा। हालांकि हाल के समय में तेलों के सस्ते होने के बाद भी भारत में तेल की कीमतें ऊपर ही रही हैं। अप्रैल की तरह अगर मई और जून में तेलों की मांग गिरती है तो फिर कीमतों को घटाने पर दबाव बन सकता है। करीबन 18 दिन बाद भारत में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वजह से इन्हें रोका गया था।

कोरोना से जंग के लिए RBI ने शुरू की खास स्कीम

50 हजार करोड़ रुपये से मजबूत किया जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पहले तो कोरोना वायरस की वजह से लोगों के परेशान होने की बात कही। वहीं साथ ही ये भी कहा कि सरकार और केंद्रीय बैंक आम आदमी समेत हर वर्ग के बारे में सोच रही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। उन्होंने आम जनता और बिजनस को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि निचले स्तर से मजबूत आर्थिक सुधार की स्थित अब पटल गई है और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना से जुड़े हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की ऑन-टैप विंडो शुरू की गई है, जिसके तहत 50 हजार करोड़ रुपये 3 साल तक की अवधि के लिए रेपो रेट पर उपलब्ध होंगे। ये स्कीम अगले साल यानी 31 मार्च 2022 तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि वह 20 मई को 35 हजार करोड़ रुपये की दूसरी गवर्नमेंट सेक्योरिटीज (g-sec) की खरीद G-SAP 1.0 के तहत करेगा।

सोने-चांदी के भाव में फिर आई जोरदार तेजी

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने और चांदी के भाव में शादियों के सीजन के साथ लगातार उतार-चढ़ाव जारी हो गया। बुधवार को सोने की कीमत में तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी के भाव में भी जोरदार उछाल आया। एमसीएक्स पर जून वायदा सोना 0.26 फीसदी की तेजी के साथ 46,993 प्रति 10 ग्राम पर था वहीं, चांदी 0.56 फीसदी बढ़कर 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम को पार गई है। अगस्त, 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गए थे। अगर देखा जाए तो सोने की कीमत रिकॉर्ड लेवल से अब तक 10000 रुपये गिर चुकी है। सोने की नई कीमतें बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा 0.26 फीसदी की तेजी के साथ 46,9937 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है. मई वायदा चांदी की कीमत 0.56 फीसदी बढ़कर 70,039 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

News यू केन USE

राज्यों में करीब 581 पीएसए चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगेः गडकरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में करीब 581 प्रेशर स्विंग ऐडसोर्प्शन (पीएसए) चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे और इन प्रतिष्ठानों में सिविल और इलेक्ट्रिकल काम पूरा करने के लिए एनएचएआई नोडल एजेंसी होगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त प्रेशर स्विंग ऐडसोर्प्शन (पीएसए) चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इस तरह के करीब स्थलों की पहचान की गयी है।' गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इन प्रतिष्ठानों में सिविल और इलेक्ट्रिकल काम पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा करेगी। उन्होंने कहा, 'हमारे इंजीनियर जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों के साथ काम करेंगे। सड़कों पर रिकॉर्ड रफ्तार के जैसे ही हम हर भारतीय की जान बचाने के लिए रिकॉर्ड रफ्तार के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे।'

कोविड को फैलने से रोकने के लिये चुनिंदा रूप से आर्थिक गतिविधियों को कम करने का सुझाव

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (एसोचैम) ने केंद्र सरकार को आर्थिक गतिविधियों को चुनिंदा रूप से कम करने की सलाह दी ताकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को कम किया जा सके। एसोचैम ने कहा कि जब तक निजी क्षेत्र दवा खरीद का कोई उचित खरीद चैनल स्थापित नहीं करता है तब तक कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति सरकारी चैनलों के माध्यम से कम से कम 90 दिनों तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। एसोचैम ने एक बयान में कहा, ''लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार को चुनिंदा रूप से आर्थिक गतिविधियों को कम करना चाहिए। सरकार को लोगों के जीवन को बचाने के लिए देश के भीतर और बाहर से हर संभव विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए।'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में एसोचैम ने सामूहिक टीकाकरण रणनीति तैयार करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात वितरण में ढील देने का भी आह्वान किया। उसने दान और आयातित उपकरण की आपूर्ति के लिए सरकार के भीतर संपर्क का एक एकल बिंदु स्थापित करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा उसने कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट का पता लगाने के लिए बड़े स्तर पर कोविड-19 के सकारात्मक जांच नमूनों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग तेज करने की भी सिफारिश की।

उज्ज्वला सिंहानिया बनीं फिक्की एफएलओ की नयी राष्ट्रीय अध्यक्ष

नयी दिल्ली। एजेंसी

उज्ज्वला सिंहानिया को फिक्की महिला संगठन (एफएलओ) का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चेंबर ने एक बयान में कहा कि उज्ज्वला महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग में भागादारी एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण में मदद कर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देंगी। उज्ज्वला ने कहा, 'मैं 19 साल से ज्यादा समय से महिलाओं के इस संगठन का हिस्सा रही हूं और संगठन का सामूहिक लक्ष्य अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, कौशल, अनुभव एवं ऊर्जा का प्रदर्शन करने के लिए महिलाओं को बढ़ावा देना और उनकी मदद करना है।' उज्ज्वला जेके इंटरनेशनल कंपनी में निदेशक हैं। यह कंपनी निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल के जरिए निवेश करती है।

अप्रैल में 3 माह के निचले स्तर पर पहुंची सेवा क्षेत्र की गतिविधियां, 54 अंक पर रहा PMI

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अप्रैल में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन, वृद्धि की रफ्तार पिछले तीन महीनों में सबसे कमजोर रही। एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को यह बताया गया। भारत सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक (PMI) अप्रैल में 54 पर रहा, जो मार्च में 54.6 पर पहुंच गया था। इस तरह पिछले महीने के मुकाबले गतिविधियां थोड़ी सुस्त रहीं। बता दें, यदि पीएमआई 50 से अधिक रहता है तो इससे गतिविधियों में तेजी का पता चलता है। पीएमआई के 50 से कम रहने का अर्थ संकुचन का संकेत देता है।

आईएचएस मार्किट (IHS Markit) की सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र) पॉलिएना डी लीमा ने कहा कि, 'कारोबार में आने वाले वर्षों में आउटपुट में वृद्धि का अनुमान है लेकिन महामारी से जुड़ी चिंताओं की वजह से कारोबारी धारणा कमजोर हुई है।' लागत व्यय के दिसंबर, 2011 के बाद सबसे तेजी से बढ़ने की वजह से सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। लीमा ने कहा कि सर्विसेज सेक्टर में सक्रिय कंपनियों ने कहा है कि उनके कुल खर्च में पिछले नौ साल में सबसे तेज दर से वृद्धि देखने को मिली है। कंपनियों ने अप्रैल में लगातार पांचवें महीने छंटनी की है। हालांकि, इसकी रफ्तार धीमी रही।

वहीं, विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, तो अप्रैल महीने में देश की विनिर्माण गतिविधियों में मामूली सुधार दर्ज किया गया। अप्रैल 2021 में यह 55.5 पर रहा, जो मार्च 2021 के 55.4 से थोड़ा ऊपर है। कोविड-19 संकट के बीच अप्रैल के पीएमआई नतीजे नए ऑर्डर और उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट को दर्शाते हैं। कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से मांग में और गिरावट आ सकती है, जबकि कंपनियां पहले ही वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी की बाधा का सामना कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की अवधि बढ़ी, अब 31 तक रहेंगी सस्पेंड

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश से चलने वाली नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अब 31 मई तक निलंबित रहेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (उउर्ँ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था।कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ये उड़ानें निलंबित हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, ''हालांकि, इस दौरान अलग-अलग मामलों को देखते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।'' कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली अनुसूचित उड़ाने निलंबित हैं। लेकिन मई के बाद से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जुलाई से चुनिंदा देशों के बीच द्विपक्षीय ''एयर बबल'' व्यवस्था के तहत कुछ उड़ानें चल रही हैं।

27 देशों के साथ एयर बबल समझौता

भारत ने केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच उनकी एयरलाइन्स द्वारा विशेष उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। डीजीसीए सर्कुलर में कहा गया है कि इस निलंबन से अंतरराष्ट्रीय माल वहन परिचालन और उसके द्वारा मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर प्रभाव नहीं होगा।

कोरोना की दूसरी लहर, 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ाः CMIE

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए 'लॉकडाउन' और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे बेरोजगारी दर चार महीने के उच्च स्तर 8 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी (सीएमआईई) ने कहा। सीएमआईई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) महेश व्यास ने कहा कि आने वाले समय में भी रोजगार के मोर्चे पर स्थिति चुनौतीपूर्ण बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में हमने 75 लाख नौकरियां गंवाई। इसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97 प्रतिशत पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 9.78 प्रतिशत जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13 प्रतिशत है। इससे पहले, मार्च में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50 प्रतिशत थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह यह दर अपेक्षाकृत कम थी। कोविड-19 महामारी बढ़ने के साथ कई राज्यों ने 'लॉकडाउन' समेत अन्य पाबंदियां लगायी हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा और फलस्वरूप नौकरियां प्रभावित हुई हैं। व्यास ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोविड-महामारी कब चरम पर पहुंचेगी, लेकिन रोजगार के मार्चे पर दबाव जरूर देखा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले 'लॉकडाउन' में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी।

फियो ने आरबीआई के निर्णय का स्वागत किया

आसान ऋण का विस्तार, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण घोषित उपायों का फियो अध्यक्ष श्री शरद कुमार सराफ ने स्वागत किया है। जिनमें आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए 50,000 करोड़ की तरलता सुविधा और अन्य सुविधायों, विशेष छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए लंबी अवधि के रेपो संचालन (एसएलटीआरओ), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एमएफआई को उधार देने, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत करने, एमएसएमई उद्यमियों को क्रेडिट और कोविड से प्रभावित होने वाले व्यक्तिगत, एमएसएमई और छोटे कारोबारियों की संपदा को दबाव से निकालने के लिए फ्रेमवर्क 2.0 शामिल है, पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन उपायों से सिर्फ सुरक्षा की भावना पैदा होने एवं तरलता चिंता ही कम नहीं होगी बल्कि पूरे देश में व्यवसायों और उद्यमियों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरबीआई के फैसले का स्वागत करते हुए फियो अध्यक्ष ने कहा कि आसान क्रेडिट उपलब्ध कराने से देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार में मदद मिलेगी जो कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संकट में है। फेडरेशन कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में सरकार के साथ खड़ा है।

मार्च, अप्रैल की जीएसटी मासिक रिटर्न, कर भुगतान में देरी पर विलंब शुल्क माफ

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिये 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और बिना किसी विलंब शुल्क के कर भुगतान करने को कहा गया है। करदाताओं को इन 15 दिनों के लिये नौ प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके

बाद यह दर 18 प्रतिशत होगी।

वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिये 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिये मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है। पहले 15 दिन के लिये ब्याज दर 'शून्य' होगी, उसके बाद यह नौ प्रतिशत की दर से ली जायेगी और 30 दिन के बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। केन्द्रीय अप्रतयक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक मई को यह अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये रियायतें 18 अप्रैल से प्रभाव में आयेंगी। इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था। कंपोजीशन डीलरों के लिये जो कि जीएसटीआर- 4 दाखिल करते हैं, वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।

एएमआरजी एण्ड एसोसियेट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कोविड महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुये सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 दो माह के लिये अनुपालन संबंधी राहतों की पेशकश की है। इस समय देश के प्रत्येक कारोबारी को अनुपालन में किसी न किसी तरह के विसतार की आवश्यकता है। ''बड़े करदाताओं को विलंब शुल्क से पूरी छूट का लाभ मिलेगा जबकि जीएसटीआर3बी दाखिल करने में 15 दिन की देरी पर ब्याज दर में आंशिक राहत दी गई है। वहीं छोटे करदाताओं को इसी तरह का लाभ 30 दिन की देरी होने पर भी मिलेगा।'' कारोबारी किसी एक महीने की बिक्री का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में उसके अगले महीने की 11 तारीख तक भर देते हैं जबकि जीएसटीआर- 3बी को अगले महीने की 20 से 24 तारीख के बीच भरा जाता है।

घर बैठे पता करें इनकम टैक्स रिफंड की स्टेटस

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आयकर विभाग बहुत तेज गति से आयकरदाताओं का इनकम टैक्स रिफंड वापस करने में लगा है। हाल ही में आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच आयकर विभाग ने 10.83 लाख आयकरदाताओं का 12,038 करोड़ रुपये इनकम टैक्स रिफंड के तौर पर वापस किया है।

NSDL
Technology, Trust & Reach

इसके बाद भी बहुत से आयकरदाता इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

सामान्यतया इनकम टैक्स रिफंड आईटीआर फाइल करने के 10 दिनों के अंदर आता है। इसलिए करदाता जो इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करने के 10 दिनों के अंदर अपनी स्थिति को चेक कर लेना चाहिए। हम आपको आज यहां पर बताएंगे कि किस तरह से आप इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर जाकर किस तरह से स्टेटस चेक करें

स्टेप-1- सबसे पहले तो ऱ्एअ्थ की वेबसाइट पर जायें।

स्टेप-2 - वेब पेज खुलने के बाद ईं- नंबर और असेसमेंट ईयर आदि का विवरण भरें।

स्टेप-3- इसके बाद आपको अपने आईटीआर की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा।

इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें।

स्टेप-1- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट को ई-फाइलिंग के लिए लॉगिन करें।

स्टेप-2- इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सिलेक्ट करें।

स्टेप-3- श्र्ब्ँम्दल्हू पर जायें. इनकम टैक्स रिटर्न्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-4- इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें।

स्टेप-5- अब आपको स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी. जो रिटर्न से संबंधित होगी. साथ में आईटीआर की स्थिति के बारे में भी पता चलेगा।

जीएसटी राजस्व अप्रैल में सर्वकालिक ऊंचाई 1.41 लाख करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्थाा की स्थिति में लगातार सुधार का संकेत मिलता है। अप्रैल 2021 में राजस्व मार्च के 1.23 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन पर जीएसटी से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) पिछले महीने की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा, ''जीएसटी राजस्व ने लगातार पिछले सात महीनों के दौरान न सिर्फ एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को सफलतापूर्वक पार किया है, बल्कि इसमें लगातार वृद्धि भी दर्ज की है। यह इस दौरान लगातार आर्थिक स्थिति में सुधार का स्पष्ट संकेत है। नकली-बिलिंग की जांच के साथ ही जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणालियों जैसे विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों के सघन डेटा एनालिटिक्स का उपयोग और प्रभावी कर प्रशासन ने लगातार कर राजस्व बढ़ाने में योगदान दिया है।'' अप्रैल 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,41,384 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा, जिसमें सीजीएसटी 27,837 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 35,621 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 68,481 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर वसूल 29,599 करोड़ रुपये के कर सहित) और उपकर 9,445 करोड़ (वस्तुओं के आयात पर पर 981 करोड़ रुपये की वसूली सहित) शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, ''देश के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद, भारतीय व्यवसायों ने एक बार फिर रिटर्न दाखिल करने संबंधी जरूरतों का पालन करने के साथ ही समय पर जीएसटी बकाया का भुगतान करके उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है।''

मेडिकल उपकरणों और दूसरे जरूरी सामानों पर घट सकता है जीएसटी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी मेडिकल उपकरणों और दूसरे सामानों पर जीएसटी घट सकता है। कुछ राज्यों ने इस पर जीएसटी घटाने की मांग रखी है। जरूरी मेडिकल आइटम्स पर जीएसटी घटाने की कई राज्यों की मांग पर विचार करने के अगले कुछ सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सकती है। पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा है कि ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी घटाने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आयोजित करना जरूरी है।

सरकार लेगी जल्द फैसला

जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्द

राज्यों ने कहा है कि जीएसटी कानून के तहत काउंसिल इस पर एक कार्यकारी फैसला कर सकती है। जीएसटी काउंसिल से जुड़े सूत्रों का मुताबिक इस बारे में जल्द बैठक बुलाई जा सकती है। काउंसिल इस पर नया एजेंडा तैयार कर रही है। अगली मीटिंग इसी महीने हो सकती है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। इस बीच, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर छह महीने की अवधि के लिए जीएसटी को हटाने की मांग की है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर जैसी जरूरी जीवनरक्षक मशीन पर जीएसटी को हटाया जाना चाहिए।

ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर पर जीएसटी 28 फीसदी से घट कर 12 फीसदी हुआ

ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। लेकिन पिछले सप्ताह इसे घटा कर 12 फीसदी कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने 3 मई को कई आयातित मेडिकल आइटमों, और दवाओं पर इंटिग्रेटेड जीएसटी को हटा दिया था। इनमें ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और फेविपिराविर जैसी दवाइयां शामिल हैं।

दूरसंचार विभाग की कंपनियों के 5जी परीक्षण को मंजूरी

परीक्षण में चीनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को 5जी परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी। हालांकि, इसमें कोई भी कंपनी चीनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग ने रिलाइंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएनएल के आवेदनों को इसके लिये मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का उपयोग नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाव सचिव अंशु प्रकाश ने कहा, ''ये परीक्षण 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी और नेटवर्क बहाल करने के समय के अंतर को कम करेगा। इससे पहले नीलामी के बाद परीक्षण हुआ था। इस बार समय का लाभ मिलेगा और दूरसंचार ऑपरेटर 5जी नेटवर्क के लिए पहले से तैयार होंगे। इससे ऑपरेटर अपने विक्रेताओं, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के प्रकार का चयन करने में सक्षम होंगे।'' उन्होंने कहा, ''भारत संचार निगम लिमिटेड अलग से परीक्षण करेगा और उनका आवेदन जल्द आएगा।''

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा दिए गए विकल्पों को विभाग ने मंजूरी दे दी है। मावेनीर के साथ साझेदारी में परीक्षण करने के वोडाफोन आइडिया के प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है और उस पर अभी निर्णय लिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने परीक्षेण के लिए तीन आवेदन जमा किए थे। इस संबंध में हुआवेई को भेजी गये ईमेल का उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

दूरसंचार विंभाग के अनुसार 5जी तकनीक 4जी की तुलना में दस गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में तीन गुना तक बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग ने 5जी परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गीयर विनिर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी-डॉट और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसका का मतलब है कि चीनी कंपनियां 5जी परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे। विभाग ने एक बयान में कहा, ''दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी। इसमें भारती एयरटेल, रिलाइंस जियोइंफोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आईडिया इंडिया लिमिटेड और एमटीएनएल शामिल हैं।'' इससे पहले भारती एयरटेल और वोडाफोन ने चीन की हुआवेई कंपनी की तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने का प्रस्ताव पेश किया था। बाद में उन्होंने हालांकि अपने आवेदन में कहा कि 5जी परिक्षण में वह चीन की किसी कंपनी की तकनीक की उपयोग नहीं करेगी। विभाग ने कहा, ''इन दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट जैसे मूल उपकरण विनिर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ करार किया है। जबकि रिलाइंस जियोइंफोकॉम लिमिटेड अपनी खुद की 5जी तकनीक का उपयोग करके यह परीक्षण करेगी।'' दूरसंचार विभाग का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार देश में शुरू होने वाली 5जी दूरसंचार सेवाओं में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने से रोक सकती है। बयान में बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को विभिन्न बैंड में प्रयोगात्मक स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसमें मिड-बैंड 3.2 गीगाहट्र्ज से 3.67 गीगाहट्र्ज़, मिलीमीटर वेव बैंड 24.25 गीगाहट्र्ज़ से 28.5 गीगाहट्र्ज़ और उप-गीगाहट्र्ज़ बैंड 700 गीगाहट्र्ज़ तक शामिल हैं। विभाग ने कहा, ''दूरसंचार ऑपरेटरों को 5जी परीक्षणों के संचालन के लिए अपने मौजूदा 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की भी अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में परीक्षणों की अवधि छह महीने की है। इसमें उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की समयावधि शामिल है।'' इसके अलावा अनुमति पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों को 5जी परिक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी करना होगा ताकि 5जी तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देशभर में उठाया जा सके।

सिडबी ने कोविड-19 से निपटने को एमएसएमई के लिए ऋण योजनाएं शुरू कीं

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सूक्ष्म, छोटे तथा मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को वित्तीय मदद देने के लिए सिडबी ने घटी ब्याज दरों वाले दो उत्पाद तैयार किए हैं, ताकि इन उद्योगों को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीमीटर जैसे अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति बढ़ने में में सक्षम बनाया जा सके।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने एक बयान में कहा कि इन योजनाओं के तहत की गयी वित्तीय सहायता से महामारी के दौरान एमएसएमई द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिडबी ने तेजी से ऋण देने के लिए दो उत्पादों की घोषणा की है, जिनमें पहला श्वास (कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सिडबी की सहायता) है। दूसरा उत्पाद आरोग (एमएसएमई को भरपाई और सामान्य वृद्धि के लिए सिडबी की सहायता) है। ये योजनाएं सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, और इनका मकसद ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषणा मुहैया कराना है। इन योजनाओं में सभी दस्तावेजों या सूचनाओं के मिलने के 48 घंटों के भीतर 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर पर दो करोड़ रुपये की राशि एमएसएमई इकाई को दी जा सकती है।

टाटा स्टील ने ऑक्सीजन आपूर्ति की दैनिक सीमा बढ़ाकर 1,000 टन की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

टाटा स्टील ने मंगलवार को कहा कि उसने कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति की दैनिक सीमा बढ़ाकर 1,000 टन कर दी है। इससे पहले, कंपनी ने 28 अप्रैल को अपने जमशेदपुर और कलिंगनर संयंत्रों से ऑक्सीजन आपूर्ति सीमा 600 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 800 टन प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। कंपनी ने ट्विटर पर लिखा है, ''टाटा स्टील ने सोमवार को 1,000 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। कंपनी अब तक विभिन्न राज्यों एवं अस्पतालों को अप्रैल तक कुल 25,700 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकी है।''कोविड-19 महामारी के बीच ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये स्टील कंपनियां कोविड मरीजों के इलाज में उपयोग को लेकर तरल रूप में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति विभिन्न राज्यों को कर रही हैं। इस्पात बनाने वाले कारखाने 'बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस' समेत स्टील बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये ऑक्सीजन बनाती हैं।

कोरोना काल में अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड, जानिए कैसे घर पर ही सेट-अप करें आईसीयू!

नई दिल्ली। एजेंसी

अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो रईस लोग अपने घर पर ही मिनी अस्पताल बना रहे हैं। देश के रईस लोग होम हेल्थकेयर (Home Healthcare) को अगले लेवल पर ले गए हैं। भले ही वह कोरोना से संक्रमित हों या फिर उन्हें संक्रमण का डर है, वह अस्पताल के आईसीयू की चीजें खरीद कर घर पर ही आईसीयू सेटअप (ICU Setup at Home) करवा रहे हैं। इसके लिए वह वेंटिलेटर (Ventilator) जैसे उपकरण भी खरीद रहे हैं। साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल्स से पहले से ही बात तय की जा रही है। आइए जानते हैं अगर घर पर ही आईसीयू सेटअप करना हो तो कैसे कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा।

मेडिकल इक्विपमेंट के साथ-साथ चाहिए क्रिटिकल केयर नर्स

एक आईसीयू सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी जैसे आईवी स्टैंड, पैरा मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, अल्फा मैट्रेस, नेबुलाइजर, डीवीटी पंप आदि। हालांकि, अलग-अलग मरीज के हिसाब से मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत अलग-अलग हो सकती है। ध्यान रहे कि अगर मरीज की हालत बहुत ही गंभीर है तो एक अनुभवी क्रिटिकल केयर नर्स की जरूरत होगी, जो मरीज की रोजाना की मेडिकल जरूरतों को पूरा कर सके, जैसे दवा देना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, इंजेक्शन देना, स्वास्थ्य बेहतर हुआ या नहीं ये चेक करना और साथ ही हर मेडिकल इक्विपमेंट को अच्छे से हैंडल करने जैसे काम देख सके।

आईसीयू बेड और फिजियोथेरेपिस्ट की हो व्यवस्था

एक मरीज को सही इलाज मुहैया कराने के लिए एक आईसीयू बेड की जरूरत होती है। मरीज के लिए किस तरह का आईसीयू बेड चाहिए होगा, यह मरीज की स्वास्थ्य की गंभीरता पर निर्भर करता है। कई बार लगातार एक ही बेड पर सोए रहने से लोगों को बेड सोर्स (कुछ जख्म) हो जाते हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इंफेक्शन के चलते हालात बहुत ही खराब हो सकती है। वहीं फिजियोथेरेपी से इंसान के शरीर की मांसपेशियों में हरकत होती है, जिससे मरीज की हालत में बेहतर सुधार होता है।

पावर बैकअप और साफ-सफाई का रखें ध्यान

जब बात क्रिटिकल इक्विपमेंट की हो रही है तो यह ध्यान रखना होगा कि आईसीयू के सभी क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट में पावर बैकअप की व्यवस्था हो, वरना सही इलाज मिलने के बावजूद मरीज की हालत गंभीर हो सकती है और कई बार नतीजे खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपने घर पर आईसीयू सेटअप किया है और उसमें किसी मरीज को रखा हुआ है तो ध्यान रहे कि उसे दिन में कम से कम 2 बार साफ करें। आईसीयू रूम में हर वक्त सही हाइजीन रखना जरूरी होता है।

आरबीआई ने केवाईसी मानदंडों में ढील दी, दिसंबर अंत तक बैंक नहीं लगाएंगे कोई रोकटोक

मुंबई। एजेंसी

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं से कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के खिलाफ दिसंबर तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध न लगाए। आरबीआई ने प्रोप्राइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के हितकारी मालिकों जैसी ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) या वी-सीआईपी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कदमों की घोषणा करते हुए कहा, ''देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के लिए जहां समय-समय से केवाईसी अपडेट (अद्यतन करने की प्रक्रिया) लंबित है, वहां ग्राहक खाते के संचालन पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक लागू न किया जाए।'' ऐसे में बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान किसी अन्य विधिक कारण को छोड़कर ग्राहक खातों पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दास ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगा कि वित्तीय हालात अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करता रहे। उन्होंने कहा, ''इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिक जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर उस हालात में सुधार के लिए काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत उपायों और नई प्रतिक्रियाओं को आजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, और भारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है।''

कोरोना का नया अवतार B1617 दक्षिण भारत में फैल रहा तेजी से ...

हैदराबाद। एजेंसी

*जहां एक ओर तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई सिरदर्द बनी हुई है, दूसरी तरफ वायरस के एक नए स्ट्रेन **B1617** ने विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। यह वायरस मौजूदा स्ट्रेन **N440K** की जगह ले रहा है। यह जानकारी सेंटर फॉर सेल्युलर ऐंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को दी। आखिर डबल म्यूटेंट कहे जाने वाले ये दोनों स्ट्रेन क्यों ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है।*

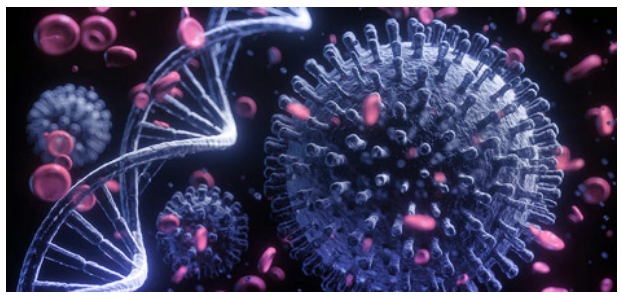

कौन से हैं डबल म्यूटेंट

सीसीएमबी के पूर्व डायरेक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि डबल म्यूटेंट की वजह से इस समय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा रोगी बीमार हुए हैं। इस साल करीब 5 हजार वैरिएंट की पड़ताल कर सीसीएमबी इस नतीजे पर पहुंचा था कि N440K दूसरे वैरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन अब B1617 इसे भी पीछे छोड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह 15 गुना ज्यादा खतरनाक है।

क्यों है ज्यादा खतरनाक

यह वैरियंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पिछले वाले स्ट्रेन से लोगों की हालत बिगड़ने में एक सप्ताह का समय लगता था। लेकिन यह नया स्ट्रेन तीन से चार दिनों में ही लोगों की हालत खराब कर रहा है। उनमें ऑक्सिजन की कमी दिखने लगती है। यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह युवाओं और बेहतर इम्युनिटी वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है।

क्या है बचाव का बेहतर तरीका

इससे बचाव का बेहतर तरीका यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जाए और जहां तक मुमकिन हो बाहर न निकला जाए।

कोरोना का नया वेरिएंट N-440K है काफी खतरनाक दूसरों की तुलना में 10 गुणा अधिक फैलने की है क्षमता

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में फैला कोरोना वायरस दुनिया में फैले कोरोना वायरस के मुकाबले 10 गुणा अधिक तेजी के साथ फैलता है और यह उसके मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट N-440K का पता लगाया है। यह B1.617 और B1.618 के बाद का आया नया वेरिएंट है। सबसे पहले इसका पता आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चला। विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्से में लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ था उसकी वजह ये वेरिएंट हो सकता है।

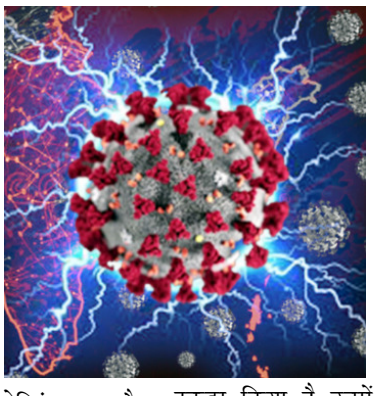

वैज्ञानिकों के मुताबिक, कोरोना का N440K वेरिएंट मुख्यतौर पर दक्षिणी राज्यों जैसे- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाया गया है। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान यह पाया- 'कोरोना के N440k वेरिएंट में A2a प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुणा अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2a प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनियाभर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440k वेरिएंट कम समय में कई गुणा अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बदले हुए स्वरूप N440K वेरिएंट में काफी कम समय में कई गुणा ज्यादा मात्रा में वायरस को फैलाने की क्षमता है। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कई केन्द्रों से उन्होंने से सैंपल इकट्ठा किया है उनमें से 50 फीसदी में कोरोना का N440k वेरिएंट पाया गया है। इसमें यह भी पता चला कि यह वायरस आबादी के एक खास हिस्से में फैल रहा है और अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं यह ज्यादा स्थानीय है।

बड़ा सवाल:

कोरोना महामारी से लोगों को कब मिलेगी आजादी? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश की जनता इस समय कोरोना की एक भयानक और खतरनाक लहर से जूझ रही है। आम जनता कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, वो हर किसी की कल्पना से परे है। पिछले कई हफ्तों में देश में कोरोना वायरस के लाखों दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर से इस महामारी से छुटकारा कब मिलेगा, क्या आमजन कभी सामान्य जिंदगी दोबारा जी पाएगा। यही नहीं लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस चरम पर पहुंच चुका है, क्या हम अभी भी पीक से थोड़ा दूर हैं, या फिर पीक को हम पछाड़ दिया है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए जानते हैं कि देश-दुनिया के डॉक्टर क्या कहते हैं...

दूसरी लहर की पीक पर या उसके बेहद करीब हैं'

नेशनल कोविड-19 सुपरमोडल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर जांच करें, जिसमें सभी संचयी आंकड़े शामिल हो, तो हम दूसरी लहर के चरम पर हैं या बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि हमने दूसरी लहर को लेकर भविष्यवाणी तो की थी लेकिन हमें खुद इसके इतने भयानक होने के बारे में जानकारी नहीं थी। हमें लगा था कि दूसरी लहर के चरम के दौरान देश में 1.2 लाख मामले आएंगे।

'जून में कोरोना की पीक देखने को मिल सकती है'

ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल के डीन डॉ. आशीष के झा के मुताबिक, कोरोना वायरस के मामले पीक पर हैं या नहीं, ये राज्यों से आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर हम महाराष्ट्र के देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पीक आ चुकी है लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में पीक आनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से जून में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से मामले बढ़े, उतनी तेजी से वो घट जाएं, इसकी गारंटी नहीं है।

'उचित तरीके से संक्रमित और मौत का आंकड़ा नहीं होगा रिपोर्ट तो पीक का पता लगाना होगा मुश्किल'

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौतम मेनन का मानना है कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील का कहना है कि अगर हम सही ढंग से मौत और संक्रमित मामलों को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पीक का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

आरोग्य सेतु एप से ही पता लग जाएगा आपने कोरोना टीका लगवाया है या नहीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आरोग्य सेतु एप जल्द ही अब आपके कोरोनावायरस की स्थिति के बारे में जानकारी दे देगा।अब तक आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल आप के संपर्क में आने वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता था।अगर कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आता था तो आरोग्य सेतु एप यह बता देता था कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे।

केंद्र सरकार आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu app) में एक फीचर लाने पर विचार कर रही है जिसमें किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस टीके की डोज ले लेने के बाद ब्लू टिक लग जायेगा।अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना टीके की दोनों डोज ले ली है तो उसके बाद उसके आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu app) में उसके नाम के सामने दो ब्लू टिक दिखेंगे। अभी इस तरह की सुविधा मैसेजिंग सेवा देने वाली कंपनी व्हाट्सएप में मैसेज डिलीवरी के बाद दिखाई देती है.

ट्रेवल करने में आसानी

इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा है कि अगले एक-दो हफ्ते में इस तरह की सुविधा शुरू की जा सकती है।एक सरकारी अधिकारी ने इस बारे में कहा, ' आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu app) में मिलने वाली इस सुविधा से फ्लाइट में चढ़ने वाले या अन्य इलाकों में ट्रेवल के लिए जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।वह अपना वैक्सीनेशन स्टेटस तुरंत दिखा सकेंगे। हर बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी करना या दिखाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है, जबकि ऐप खोलने में ऐसी कोई समस्या नहीं आती.'

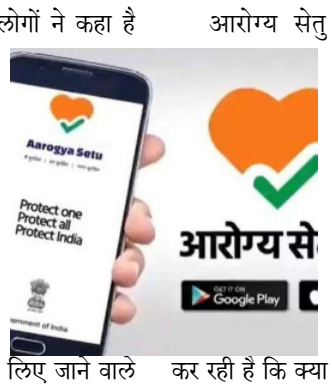

नजर रखने की जरूरत नहीं

आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu app) में मिलने वाली सुविधा की वजह से एक बार कोरोना संकट की स्थिति सामान्य होने के बाद लोगों को दफ्तर जाने में भी आसानी हो जाएगी।सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या कोरोनावायरस वैक्सीन के दो डोज ले लेने वाले व्यक्ति के कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है या नहीं।वास्तव में अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो सरकार नहीं चाहती कि उस व्यक्ति के लोकेशन या अन्य चीजों की जानकारी जुटाई जाती रहे।सरकारी अधिकारी ने कहा, 'यह वास्तव में एक नीतिगत फैसला है और इस बारे में अंतिम निर्णय लेने में समय लग सकता है.'

कोविन एप का अपग्रेडेशन

इसके साथ ही सरकार अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन ऐप कोविन (CoWin) को भी अपग्रेड करने में जुटी है जिससे कि लोग आसानी से टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक कर सकें। कोविन प्लेटफार्म (CoWin platform) के लिए बैकग्राउंड वर्क पर अभी काम चल रहा है और इसमें तीसरी वैक्सीन भी जोड़ी जा रही है। इस हफ्ते ही रूस से कोरोनावायरस वैक्सीन स्पूतनिक V की पहली खेप आ चुकी है।यह भी लोगों के लिए जल्द शुरू हो जाएगी।सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते में यह टीका भी लोगों को लगना शुरू हो जाएगा।कोविन ऐप (CoWin App) पर 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिससे कि उन्हें कोरोनावायरस का टीका लग सके. पिछले हफ्ते शुरू हुए इस अभियान के बाद अब तक कोविन (CoWin) पर 5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं।देश में कोरोना संक्रमण के सेकंड वेव की स्थिति गंभीर होती जा रही है और इस बीच सरकार ने कोरोनावायरस टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया है.

अच्छी आदतें होंगी तो अच्छे दिन भी आएंगे, जानिए शनिदेव को कौन सी बातें पसंद हैं

शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आपमें यह 22 आदतें हैं तो मान कर चलिए कि शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे उल्टे आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव रहने वाली है। हर संकट में वे आपके साथी बनकर राह दिखाएंगे। जानिए वे आदतें कौन सी हैं...

1.नाखून काटते रहें

जो लोग रोज अपने नाखून काटते हैं और उन्हें साफ भी रखते हैं, शनि ऐसा करने वालों का हमेशा खयाल रखते हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने नाखून काटने में आलस करने लगें या आपके नाखून गंदे रहने लगे तो समझें कि आपको शनि दशा सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए। नाखून काटने की आदत को कभी ना बदलें।

2.दान करते रहें

अगर आपका दिल गरीबों, जरूरतमंदों को देखकर पसीज जाता है और हर तीज-त्योहार पर गरीब जरूरतमंद की आप मदद करते हैं तो समझें शनिदेव की आप पर विशेष कृपा है। अगर आप गरीबों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और कपड़े सच्चे मन से दान करते हैं, तो आश्वस्त रहिए कि शनिदेव आपका हमेशा कल्याण ही करेंगे।

3.छाते की भेंट देगी शनिदेव की छत्र-छाया

धूप व बारिश से बचने के लिए छाते दान करने वालों पर शनिदेव की छत्र-छाया हमेशा बनी रहती है। अगर अब तक यह आदत नहीं थी तो इसे तुरंत अपनी अच्छी आदतों में शामिल कर लीजिए। आखिर शनिदेव की छत्र-छाया किसे नहीं चाहिए?

4.कुत्तों की सेवा

कुत्तों की सेवा करने वालों से भगवान शनि हमेशा प्रसन्न होते हैं। कुत्तों को खाना देने वालों और उनको कभी ना सताने वालों के शनिदेव सभी कष्ट दूर करते हैं। इसलिए अगर आप भी कुत्तों को प्यार करते हैं तो जीवन में शनि कोप से सदा बचे रहेंगे।

5.नेत्रहीन को राह दिखाएं

किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को राह दिखाना, उनकी मदद करना शनि को खुश करने में सहायक सिद्ध होता है। जो लोग भी नेत्रहीन लोगों की अनदेखी नहीं करते, उनकी निःस्वार्थ मदद करते हैं, शनिदेव उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सफलता-उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

6.शनिवार का उपवास

शनिवार का उपवास रखकर अपने हिस्से का भोजन गरीबों को देने की आदत है तो समझें शनि की कृपा से अन्न के भंडार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन भर इस नियम का पालन करते हैं तो उन्हें कभी धन-संपदा की कमी नहीं होती।

7.मछलियों को आहार

जो मछली खाते नहीं है बल्कि मछलियों को खाना खिलाते हैं उनसे शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी मछलियों को दाना खिलाने की आदत है तो खुशकिस्मत हैं आप, अपनी इस आदत को छूटने ना दें।

8.हर दिन स्नान, साफ स्वच्छ रहने की आदत

प्रतिदिन स्नान कर खुद को साफ रखने वालों पर शनि की कृपा होती है। पवित्र रहने वालों की शनि हमेशा मदद करते हैं।

9.सफाई-कर्मियों की मदद

जो सफाई-कर्मियों का सम्मान करते हैं और उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं, शनिदेव उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह आदत कभी न बदलें, भाग्यशाली बनने की राह यही आदत खोलेगी। शनिदेव इस आदत से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।

10.साथी हाथ बढ़ाना

जो लोग जरूरतमंद, परेशान और मेहनतकश लोगों की यथासंभव मदद करते हैं, वे शनिदेव को बेहद पसंद होते हैं। शविदेव उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। इसलिए मदद करने की अपनी आदत को सदा बने रहने दें।

11.सम्मान करने की आदत

वृद्ध माता-पिता तथा स्त्रियों को मां समान मानकर उनका सम्मान करने वालों की शनिदेव हमेशा सहायता करते हैं।

12.पौधारोपण, और पीपल-बरगद का पूजन

पौधारोपण व पेड़ों का पूजन शनि भगवान को खुश करने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग पीपल और बरगद की पूजा करते हैं उनपर शनि अपनी कृपा अक्षुण्ण बनाए रखते हैं।

13.शिव की पूजा

भगवान शिव की पूजा शनि को प्रसन्न करती है। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने वालों का शनि सदैव ध्यान रखते हैं।

14.पितरों का श्राद्ध

जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनसे प्रसन्न होकर शनिदेव उनके कष्ट दूर करते हैं। इसलिए यह आदत हमेश बरकरार रखें।

15.ईमानदारी से आजीविका

ऐसे लोग जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सही और धर्म की राह पर चलकर धन अर्जित करते हैं उन्हें शनि अपार लक्ष्मी का वर देते हैं। जो लोग ब्याजखोरी करते हैं, उनसे शनि रुष्ट हो जाते हैं। ब्याजखोरी से बचने वालों की शनि हमेशा सहायता करते हैं।

16.हनुमान आराधना

जिनके ईष्ट भगवान हनुमान होते हैं या जो हनुमान को ईष्ट देवता बनाता है शनिदेव उसके रक्षक बनकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं।

17.कान्हा के दोस्त हैं शनि

जो श्रीकृष्ण को अपना ईष्ट भगवान मानते हैं शनि उनके दोस्त बन जाते हैं और कभी उनपर कोई विपत्ति नहीं आने देते।

18.दिव्यांगों की मदद

दिव्यांगों की सहायता करना शनिदेव को प्रसन्न करता है। ऐसे लोगों का शनि सदैव कल्याण करते हैं। शनि स्वयं एक पैर से शनैः शनैः चलते हैं अतः यथासंभव दिव्यांगों की मदद की आदत डालें।

19.शराब से दूरी

शराब का सेवन शनिदेव को नाराज करता है। जो लोग मदिरापान से दूर रहते हैं शनिदेव की कृपा उनपर बनी रहती है।

20.शाकाहार की आदत

जो लोग शाकाहार का सेवन करते हैं और मांस, मछली, मीट से दूर रहते हैं उनसे शनिदेव प्रसन्न होकर उनके परिवार समेत उनका भला करते हैं।

21.सातमुखी रुद्राक्ष

सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों के शनिदेव भाग्य खोल देते हैं। इसलिए जिन्हें रुद्राक्ष पसंद हो या रुद्राक्ष पहनने की आदत हो, वे शनिदेव से शुभ फल पाते हैं।

22.कुष्ठ रोगियों की मदद

कुष्ठ रोगियों की सेवा करना पुण्य का काम माना गया है। शनि भी ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को सारे कष्टों, परेशानियों से शनिदेव बचाते हैं।

मिश्री के बने शिवलिंग की पूजा करने से होता है रोगों का नाश

शिवपुराण अनुसार भगवान विष्णु ने पूरे जगत के सुख और कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा को अलग-अलग तरह के शिवलिंग बनाकर देवताओं को देने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अलग-अलग पदार्थों, धातु व रत्नों से शिवलिंग बनाए। जैसे पारद, मिश्री, जौं चावल, भस्म, गुड़, फल फूल, स्वर्ण रजत, बिबर मिट्टी, दही, मक्खन, हीरे, मोती, मणि, मूंगा, नाग, पार्थिव, तांबा, इंद्रनील, पुखराज, पद्मराग, पीतल, लहसुनिया, रत्न, चंदन, स्फटिक आदि से शिवलिंग बनाए गए।

सभी शिवलिंग के नाम भी अलग-अलग दिए गए और सभी का प्रभाव भी अलग-अलग बताया गया। शिवलिंग बनाने के बाद सभी की श्रेणियां भी रखी गई। जैसे, देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग, स्वयंभूलिंग। आओ जानते हैं कि मिश्री के शिवलिंग की पूजा करने के क्या लाभ हैं।

मिश्री शिवलिंगः-

1. चीनी या मिश्री से बने शिवलिंग को मिश्री शिवलिंग कहा जाता है।
2. कहते हैं कि इस की पूजा करने से रोगों का नाश होकर पीड़ा से मुक्ति मिलती हैं।
3. यदि आपके घर परिवार में किसी को किसी भी प्रकार का रोग है या तबियत खराब है तो रोजाना मिश्री से बने शिवलिंग की विधिवत पूजा करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है।
4. इस शिवलिंग को बनाने की विधि, पूजा विधि और मंत्र को अच्छे से किसी जानकार से पूछकर ही विधिवत पूजा करें।

चल रहा है वैशाख महीना, 26 मई तक करें पुण्य कमाने के सरल उपाय

वैशाख माह हिन्दू पंचांग का दूसरा महीना होता है। यह महीना 28 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 26 मई को समाप्त होगा। नारद जी के अनुसार, इस माह को ब्रह्मा जी ने सभी माह में श्रेष्ठ बताया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, वैशाख मास में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान-दान का महत्व है। इस मास में कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को कई तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये उपाय इस प्रकार है-

राहगीरों को पिलाएं जल

वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है, उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से दस हजार राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है।

प्याऊ लगवाना

जो व्यक्ति वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि-मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण की कृपा बनी रहती है।

पंखा दान करना

धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवाकर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु का सामिप्य प्राप्त कर लेता है। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है।

अन्न दान

अन्न दान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।

पादुका एवं चटाई

शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते-चप्पल दान करता है,वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुःख का नाश होता है,निद्रा से थकावट दूर होती है इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने उद्योग की 10,900 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिये दिशानिर्देश जारी किया है। क्षेत्र की वृद्धि के लिये इस योजना की घोषणा हाल ही में की गयी है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिये 'ऑनलाइन पोर्टल' की शुरूआत की।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये 10,900 करोड़ रुपये के व्यवव आवंटन के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अग्रणी खाद्य विनिर्माण कंपनियां तैयार करने में मदद करना तथा खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ाना है। मंत्रालय ने तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना के अंतर्गत विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।

पहली श्रेणी में, आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और एक सामान्य आवेदन के साथ योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी के तहत नवोन्मेषी और जैविक उत्पाद बनाने वाले एसएमई आवेदक बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में विदेशों में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत बिक्री आधारित प्रोत्साहन 2021-22 से 2026-27 तक यानी छह साल के लिये आधार वर्ष के मुकाबले बढ़ी हुई बिक्री पर दिया जाएगा। बढ़ी हुई बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। पांचवें और छठे साल के लिये यह क्रमशः 2021-22 और 2022-23 होगा।

किसी खास फल के पीछे मत भागिए

आपके घर में फलने वाले आम से भी बूस्ट होती है इम्युनिटी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फलों का राजा आम (Mango) अपने बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए तो लोकप्रिय है ही। इसका पेड़ भी इम्युनिटी बढ़ाने के लिए हीलिंग बायोएक्टिव यौगिकों का अद्भुत भंडार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली (Immunity) को मजबूत रखना एक सामान्य व्यक्ति और साथ ही मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं जैसी जीवन शैली आधारित समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए एक प्राथमिकता है। ऐसे में आम का पेड़ सहायक हो सकता है।

आम के पेड़ में पाया जाता है मेंगिफेरिन

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के निदेशक डा. शैलेंद्र राजन का कहना है कि मेंगिफेरिन प्राकृतिक एंटी-वायरल यौगिकों में से एक है जो आम के पेड़ के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसका उपयोग कई देशों में औषधीय और स्वास्थ्य सप्लीमेंट तैयार करने के लिए किया जा रहा है। आम के फल, पत्ती और तना मेंगिफेरिन का एक समृद्ध स्रोत है। यह एक बायोएक्टिव यौगिक है, जो अपने एंटी-वायरल, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-एथेरोस्क्लेरोटिक गुणों के लिए जाना जाता है जिसमें हृदय और मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदे शामिल हैं। यह एचआईवी वायरस के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है।

इम्यूनिटी के लिए आम आधारित उत्पाद

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (ABI) द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आम आधारित दो उत्पाद विकसित किए गए हैं। संजीवनीप्राश (शुगर फ्री च्यवनप्राश) और मैंगीफ्लेक्स (ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट) में आम के बायोएक्टिव यौगिकों को संयोजित किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले आयुर्वेदिक उपायों में से च्यवनप्राश की सिफारिश की है। संजीवनीप्राश का शुगर फ्री होना मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित है। इसमें च्यवनप्राश के अतिरिक्त इम्युनिटी बढ़ाने वाले मेंगिफेरिन और अन्य बायोएक्टिव यौगिकों का भी योगदान है। संजीवनीप्राश में च्यवनप्राश का प्रभाव मेंगिफेरिन की सहायता से बढ़ाया गया है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत करने में मदद करता है।

ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट कोविड-19 से लड़ने में सहायक

शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट कोविड-19 के साथ गंभीर रूप से बीमार रोगियों में श्वसन और गुर्दे की क्रियाशीलता संबंधित मापदंडों में सुधार करता है। चीनी वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि उच्च ओमेगा 3 फैटी एसिड स्तर रोगियों में कम मृत्यु दर से जुड़ा है। पोषण पर चीनी विशेषज्ञ पैनल ने प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और पॉलीफेनोल के सेवन को बढ़ाने की सलाह दी थी। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन कोविड-19 रोगियों में मृत्य दर को कम कर सकता है जबकि प्रोटीन शरीर में अपचय घटाने और पॉलिफिनॉल्स इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करते हैं।

आम में अन्य विटामिन भी

आम एवं मोरिंगा आधारित उत्पाद विटामिन ए, सी और ई, और अन्य बायोएक्टिव यौगिकों में समृद्ध हैं। मोरिंगा मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए जाना माना स्रोत है। इसके पत्ते मजबूत प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए उत्तम प्राकृतिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। संस्थान के ए बी आई द्वारा मोरिंगा आधारित उत्पाद को मेंगिफेरिन और अन्य आम आधारित बायोएक्टिव यौगिकों ने और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। आम आधारित यह उत्पाद न केवल मेंगिफेरिन में समृद्ध हैं, बल्कि अन्य लाभकारी बायोएक्टिव यौगिक जैसे ल्यूपॉल और एलीजिक एसिड युक्त हैं। अब, इन बायोएक्टिव यौगिकों को कैंसर रोधी होने के अलावा अनेक औषधीय गुणों युक्त माना जाता है।

केंद्र ने पांच राज्यों से 2021 खरीफ सत्र में प्याज का रकबा 9,900 हेक्टेयर बढ़ाने को कहा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र ने शुक्रवार को राजस्थान सहित प्याज की खेती करने वाले पांच राज्यों से आगामी खरीफ सत्र के दौरान इस फसल के रकबे में 9,900 हेक्टेयर की बढ़ोतरी करने को कहा, ताकि किसी भी मूल्य वृद्धि की स्थिति से बचा जा सके। खरीफ के सत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख प्याज उगाने वाले राज्य हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश गैर-पारंपरिक रूप से प्याज उगाने वाले राज्य हैं। सरकार ने प्याज की नियमित रूप से बड़े पैमाने पर खेती नहीं करने वाले राज्यों से ही प्याज का उत्पादन बढ़ाने को कहा है।

कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने राज्य सरकारों के साथ एक सम्मेलन में गैर-पारंपरिक राज्यों में खरीफ सत्र के दौरान प्याज का रकबा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) के आगामी खरीफ सत्र के लिए एक रणनीति तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पारंपरिक प्याज उगाने वाले क्षेत्रों में उपलब्धता प्रभावित होती है, तो इससे मदद मिलेगी। उन्होंने पांच गैर-पारंपरिक प्याज उगाने वाले राज्यों को इस साल के खरीफ सत्र में प्याज का रकबा बढ़ाकर 51,000 हेक्टेयर करने के लिए कहा, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि में 41,081 हेक्टेयर था।

वर्ष 2020-21 के अक्टूबर-अप्रैल में चीनी उत्पादन दो करोड़ 99.1 लाख टन हुआः इस्मा

नयी दिल्ली। एजेंसी

चीनी उद्योग के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने सोमवार को कहा कि विपणन सत्र 2020-21 के अप्रैल महीने तक देश का चीनी उत्पादन दो करोड़ 99.1 लाख टन तक पहुंच गया है। इस्मा ने कहा कि चीनी निर्यात के संबंध में, चीनी मिलों ने अब तक 54 से 55 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध किया है। इसमें से 35 लाख टन का निर्यात किया गया है, जबकि इस महीने तक 10 लाख टन का और निर्यात किये जाने की उम्मीद है। एथेनॉल के बारे में इस्मा ने कहा कि चीनी मिलों ने इस साल के 19 अप्रैल तक तेल विपणन कंपनियों को 117.72 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की है, जबकि कुल अनुबंधित मात्रा 302.53 करोड़ लीटर है। अद्यतन उत्पादन के आंकड़े जारी करते हुए, इस्मा ने कहा कि देश भर की चीनी मिलों ने वर्ष 2020-21 के विपणन सत्र (अक्टूबर-सितंबर) की अक्टूबर-अप्रैल अवधि के दौरान दो करोड़ 99.1 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है।

इस्मा ने विपणन सत्र 2020-21 में चीनी उत्पादन 3.02 करोड़ टन होने का अनुमान जताया है, जो पिछले सत्र के दो करोड़ 74.2 लाख टन के उत्पादन से अधिक है। इस्मा के आंकड़ों के अनुसार, देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन इस साल अप्रैल तक एक करोड़ 5.6 लाख टन से थोड़ा कम है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह उत्पादन एक करोड़ 16.5 लाख टन था। जबकि देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक महाराष्ट्र में उत्पादन पिछले साल के 60.9 लाख टन से बढ़कर इस बार की समान अवधि में एक करोड़ 5.6 लाख टन हो गया।

इसी तरह, देश के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में चीनी उत्पादन इस साल अप्रैल तक बढ़कर 41.6 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 33.8 लाख टन था। इन प्रमुख उत्पादक राज्यों की अधिकतर चीनी मिलों द्वारा अगले एक पखवाड़े में अपना परिचालन बंद करने की आशंका है। कर्नाटक में, जुलाई के शुरू होने वाले विशेष सत्र में कुछ चीनी मिलें काम कर सकती हैं।

बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा ने पहले ही पेराई कार्य बंद कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में एक-एक मिल चल रही है। चीनी निर्यात के बारे में, इस्मा ने कहा कि इस वर्ष के दौरान अनिवार्य निर्यात के लिए और घरेलू बिक्री के लिए आवंटित चीनी के कोटे को अदला बदली करने के सरकार के निर्णय की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। एथेनॉल के बारे में, देश में औसतन 7.36 प्रतिशत पेट्रोल के साथ एथेनॉल सम्मिश्रण के स्तर को प्राप्त कर लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे 11 राज्यों ने 10 प्रतिशत तक उच्च सम्मिश्रण किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

मार्च तिमाही में दोगुना से अधिक बढ़ा मुनाफा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में दोगुना से अधिक बढ़कर 13,227 करोड़ रुपये रहा। खुदरा क्षेत्र के उपभोक्ता कारोबार और दूरसंचार तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में तिमाही आधार पर सुधार से कंपनी का लाभ बढ़ा है। हालांकि रिफाइनिंग कारोबार में सुस्ती जारी है।

कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में उसे 6,348 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी को अमेरिकी शेल संपत्ति की बिक्री से 797 करोड़ रुपये का अपवादस्वरूप लाभ हुआ, जो चौथी तिमाही के परिणाम में शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय आलोच्य तिमाही में 13.6 प्रतिशत बढ़कर 1,72,095 करोड़ रुपए रही।

कंपनी का तेल और रसायन कारोबार तिमाही आधार पर बेहतर हुआ, लेकिन एक साल पहले इसी तिमाही में कमाई कम हुई है। इसका कारण महामारी के कारण ईंधन मांग कम होने से रिफाइनिंग करोबार में सुस्ती है। इसकी भरपाई दूरसंचार और खुदरा कारोबार ने किया जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों का कमाई में योगदान अब 45 प्रतिशत हो गया है जो एक साल पहले 33 प्रतिशत था।

कंपनी की दूरसंचार इकाई जियो का शुद्ध लाभ मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 47.5 प्रतिशत बढ़कर 3,508 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने शुद्ध रूप से 1.54 करोड़ से अधिक ग्राहक जोड़े। हालांकि इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज शून्य कर

उसकी जगह बिल एंड कीप (बिल काटने,अपने पास ही रखने) की जनवरी2021 से लागू नयी व्यवस्था अपनाये जाने से प्रति उपभोक्ता कमाई घटकर 138 रुपये प्रति माह पर आ गयी जो इससे पूर्व तिमाही में 151 रुपये प्रति माह थी।

किराना कारोबार से रिकॉर्ड आय और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में मजबूत वृद्धि से खुदरा कारोबार का कर पूर्व लाभ 41 प्रतिशत बढ़कर 3,623 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने इस दौरान 826 नये स्टोर जोड़े, जिससे उसके दुकानों की संख्या बढ़कर 12,711 पहुंच गयी। हालांकि कोविड संक्रमण बढ़ने से कंपनी क खुदरा कारोबार अप्रैल में प्रभावित हुआ है। इस दौरान ग्राहकों के स्टोर में आने की संख्या 35 से 40 प्रतिशत कम हुई है।

पेट्रोरसायन मार्जिन में सुधार बना हुआ है। लेकिन कोविड के कारण रिफाइनरी निम्न क्षमता पर काम कर रही है। इससे तेल और रसायन कारोबार का कर पूर्व लाभ (ईबीआईटीडीए) 4.6 प्रतिशत घटकर 11,407 करोड़ रुपए रहा। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध लाभ करीब 35 प्रतिशत बढ़कर 53,739 करोड़ रुपये रहा जबकि आय 18.3 प्रतिशत बढ़कर 5,39,238 करोड़ रुपए रही।

वित्तीय परिणाम के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने तेल और रसायन तथा खुदर क्षेत्र में अच्छा सुधार दर्ज किया है। जबकि डिजिटल सेवा कारोबार (रिलायंस जियो समेत) में मजबूत वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट से जहां एक तरफ आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा है, रिलायंस ने करीब 75,000 लोगों को नौकरियां दी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया।

अंबानी ने कहा कि यह भारत के लिए असाधारण चुनौतियों वाला समय है। हमारी इस समय प्राथमिकता देश और समुदाय को कोविड संकट से बाहर निकालने की है। हमने महामारी की रोकथाम के लिये चलाये जा रहे अभियान को मजबूती प्रदान करने को लेकर अपना बेहतरीन संसाधन लगाया है। जामनगर स्थित हमारे संयंत्र चिकित्सा में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं, जो इस समय कई राज्यों के लिये काफी महत्वपूर्ण है। कंपनी का सकल कर्ज मार्च 2021 के अंत में घटकर 2,51,811 करोड़ रुपए पर आ गया जो दिसंबर 2020 के अंत में 2,57,413 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी के पास नकद राशि बढ़कर 2,54,019 करोड़ रुपए पहुंच गई जो इससे पहले, 2,20,524 करोड़ रुपए थी।

ग्लेनमार्क ने भारत में एक किफ़ायती मूल्य पर लॉन्च की रयालट्रिस-एझेड

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक एकीकृत दवा कंपनी, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने भारत में मध्यम से गंभीर एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार के लिए रयालट्रिस-एझेड (Ryaltris®-AZ) नेज़ल स्प्रे लॉन्च करने की घोषणा की। श्वसन क्षेत्र के अग्रणियों में से एक ग्लेनमार्क, भारत में एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार के लिए किफ़ायती मूल्य पर ब्रांडेड जेनेरिक संस्करण लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। इससे मरीजों को देश में कहीं अधिक सुविधाजनक, किफ़ायती उपचार का विकल्प मिलेगा।

ग्लेनमार्क रयालट्रिस-एझेड (Ryaltris®-AZ) को मोमेटसनफ्यूरोएट 50 एमसीजी (Mometasonefuroate50 mcg) + एज़िलास्टाइन 140 एमसीजी (Azelastine 140 mcg) को एक नये निश्चित खुराक संयोजन के रूप में लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 20-30इ भारतीय आबादी एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है। इसके अलावा, भारत में, रोगियों को दवा का खर्च अपने दम पर वहन करना पड़ता है और इसलिए दवा की कीमत एक प्रमुख कारक बन जाती है जो उपचार अनुपालन को प्रभावित करती है। जहां समान दवा श्रेणी के शीर्ष 10 मौजूदा ब्रांड की चिकित्सा की औसत लागत रु. 365 है, ग्लेनमार्क को रयालट्रिस-एझेड (Ryaltris®-AZ) नेज़ल स्प्रे को रु. 175/- प्रति 75 मीटर्ड खुराक (एमडी) विशेष मूल्य पर लॉन्च किया गया है। यह मूल्य बाज़ार में समान दवा श्रेणी के शीर्ष 10 ब्रांडों की औसत कीमत की तुलना में लगभग 52% कम है।

ग्लेनमार्क द्वारा विकसित रयालट्रिस-एझेड,(Ryaltris®-AZ) नेज़ल स्प्रे एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड का एक नया निश्चित खुराक संयोजन वाला नेज़ल स्प्रे है, जो 12 साल से ऊपर की आयु के रोगियों में एलर्जिक राइनाइटिस (एआर) से जुड़े लक्षणों के उपचार के लिए निर्दिष्ट है। यह एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों, जिसमें बंद नाक, नाक बहना, नाक में खुजली, छींक के साथ-साथ आंख लाल होना, खुजली और आंखों से पानी बहने से राहत देता है।

आलोक मलिक, ग्रुप उपाध्यक्ष और बिजनेस हेड, इंडिया फॉर्मूलेशन्स का कहना है, 'ग्लेनमार्क भारत में श्वसन संबंधी रोग के मरीज़ों के लिए नवीनतम उपचार विकल्पों तक पहुंचाने में अग्रणी रहा है। हमें देश में मरीजों के लिए किफ़ायती मूल्य पर, हमारे ब्रांड रयालट्रिस-एझेड (Ryaltris®-AZ) पेश करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है, जिस पर मेडिकल अध्ययन किया गया है और जो अत्याधुनिक है। श्वसन क्षेत्र ग्लेनमार्क के लिए फोकस का एक मुख्स क्षेत्र है और इस उत्पाद के लॉन्च हमें भारत में मरीजों को एक प्रभावी, सुविधाजनक, विश्वस्तरीय और किफ़ायती उपचार विकल्प देकर एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार तक पहुंच को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगा।'

रिलायंस ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन प्रतिदिन 1000 टन तक बढ़ा, 24 टैंकर विमानों से मंगवाए

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने जामनगर तेल रिफाइनरी में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन 1000 टन से अधिक कर दिया है। आरआईएल ने एक बयान में कहा कि यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है।

कंपनी ने दावा किया कि रिलायंस आज भारत की करीब 11इ मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है और हर दस में से एक रोगी को उसके द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन दी जा रही है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, और जेट ईंधन जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं, यहां मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर रिलायंस ने मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया।

बयान में कहा गया कि रिलायंस ने ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को पुख्ता करने के लिए सऊदी अरब, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और थाईलैंड से 24 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर के (विमानोंसे) मंगाए हैं, जिससे देश में लिक्विड ऑक्सीजन की कुल परिवहन क्षमता में 500 टन का इजाफा हुआ है। कंपनी ने बताया कि टैंकर एयरलिफ्ट करने में भारतीय वायुसेना का भी सहयोग रहा। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, ''जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ रहा है तब मेरे लिए और रिलायंस में हम सभी के लिए, जीवन बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। भारत में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के उत्पादन और परिवहन क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।'' रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, ''रिलायंस फाउंडेशन में हम मदद की हर संभव कोशिश करेंगे। हर जीवन अनमोल है। हमारी जामनगर रिफाइनरी और संयंत्र को रातोंरात बदल दिया गया है ताकि भारत में मेडिकल ग्रेड तरल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।